Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

16 अगस्त 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने नई दिल्ली में आगामी "भारत स्टील 2026" शिखर सम्मेलन के लिए लोगो, ब्रोशर और वेबसाइट का अनावरण किया।

14 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक उच्च-स्तरीय कार्यक्रम में, केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने "भारत स्टील 2026" के लोगो, ब्रोशर और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का आधिकारिक रूप से अनावरण किया। यह घोषणा इस्पात मंत्रालय के तत्वावधान में भारत के प्रमुख इस्पात उद्योग शिखर सम्मेलन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

• 10 जून, 2024 को इस्पात मंत्रालय (भारी उद्योग के अतिरिक्त) का कार्यभार संभालने के बाद से, केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी—जिन्हें आधिकारिक तौर पर हरदनहल्ली देवेगौड़ा कुमारस्वामी के नाम से जाना जाता है—ने डिजिटल नवाचार और आयोजन-आधारित पहुँच को अपनाकर इस्पात क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। इससे पहले, 16 मई, 2025 को उद्योग भवन में इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट का शुभारंभ करके, उन्होंने बहुभाषी पहुँच, साइबर सुरक्षा उन्नयन और भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देशों (GIGW) के अनुपालन के माध्यम से पारदर्शिता, सुगमता और हितधारक जुड़ाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की।

• "भारत स्टील 2026" 16-17 अप्रैल, 2026 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा—यह एक प्रतिष्ठित स्थल है जहाँ उत्कृष्ट मेट्रो कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लिए आसान पहुँच है। हाल ही में अनावरण की गई ब्रांडिंग और ब्रोशर, इस आयोजन के नवाचार, स्थिरता और वैश्विक नेटवर्किंग पर केंद्रित होने की एक स्पष्ट झलक प्रस्तुत करते हैं—जो भारत को वैश्विक इस्पात उद्योग में एक अग्रणी वास्तुकार के रूप में स्थापित करता है।

• वक्ताओं के रूप में शामिल प्रमुख हस्तियों में स्वयं केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी, इस्पात राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा, इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री संदीप पौंड्रिक, अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार श्री आशीष चटर्जी, और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उद्यमों के प्रमुख—स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL), NMDC, MSTC, MECON के CMD—और अन्य शामिल हैं। इनका समावेश शिखर सम्मेलन के विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय और शीर्ष नेतृत्व के साथ समन्वय को रेखांकित करता है।

Key Points:-

(i) पहले के डिजिटल परिवर्तन प्रयासों के बाद, यह ब्रांडिंग लॉन्च, नीतिगत दृश्यता और बाज़ार जुड़ाव बढ़ाने की मंत्रालय की रणनीति का एक हिस्सा है। इस्पात मंत्रालय, जो भारत सरकार के अधीन कार्य करता है और जिसका उद्देश्य नवाचार, नीति निर्माण और क्षमता विस्तार को बढ़ावा देकर भारत को इस्पात के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाना है, ऐसे प्रचार मंचों से लाभान्वित होता है।

(ii) JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर (JSPL), आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया और जिंदल

स्टेनलेस (JSL) जैसे प्रमुख उद्योग घरानों के सशक्त प्रायोजन और अखिल भारतीय इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन तथा स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन सहित प्रमुख उद्योग संघों के समर्थन के साथ, यह आयोजन एक सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डालता है। इसे इस्पात उत्पादकों, वैश्विक खरीदारों, बुनियादी ढाँचा विकासकर्ताओं, तकनीकी नवप्रवर्तकों ("स्मार्ट स्टील टेक्नोलॉजीज़" जैसे सत्रों के माध्यम से) और सरकारी हितधारकों के लिए एक अनिवार्य मंच के रूप में स्थापित किया गया है।

(iii) मोटे तौर पर, भारत स्टील 2026 के लिए लोगो, ब्रोशर और वेबसाइट का शुभारंभ भारत के रणनीतिक औद्योगिक दृष्टिकोण और आधुनिक संचार विधियों के सम्मिलन को दर्शाता है। पारंपरिक नेतृत्व सहभागिता को डिजिटल पहुँच और सु-ब्रांडेड आयोजन अवसंरचना के साथ जोड़कर, मंत्रालय वैश्विक इस्पात उद्योग में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा के लिए आधार तैयार कर रहा है।

2. भारत ने अनुमोदित मॉडल और निर्माताओं की सूची (ALMM) के तहत 100 गीगावाट सौर PV मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता हासिल की है।

अगस्त 2025 में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने घोषणा की कि भारत ने अनुमोदित मॉडल और निर्माताओं की सूची (ALMM) के तहत 100 गीगा वाट (GW) सौर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता का ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल कर लिया है, जो 2014 में 2.3 गीगावाट से एक बड़ी छलांग है।

- **अपनी घोषणा में, प्रल्हाद जोशी ने ज़ोर देकर कहा कि यह उपलब्धि अक्षय ऊर्जा निर्माण क्षमताओं में भारत की तीव्र प्रगति को दर्शाती है और भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के अनुरूप है। 2014 में 2.3 गीगावाट से 2025 में 100 गीगावाट तक की वृद्धि, एक दशक से लगातार नीतिगत समर्थन और उद्योग वृद्धि को दर्शाती है।**

- **यह विकास भारत की स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों, विशेष रूप से 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। ALMM ढांचा घरेलू उद्योग के विकास को बढ़ावा देते हुए सौर PV विनिर्माण में गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय उपकरण रहा है।**

- **सौर PV मॉड्यूल के लिए मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची (ALMM) MNRE द्वारा ALMM ऑर्डर 2019 के माध्यम से पेश की गई थी, जो 2 जनवरी, 2019 से प्रभावी थी। पहली ALMM सूची मार्च 2021 में जारी की गई थी, जिसमें लगभग 8.2 गीगावॉट की प्रारंभिक संयुक्त क्षमता वाले निर्माताओं को सूचीबद्ध किया गया था।**

Key Points:-

(i) पिछले कुछ वर्षों में, सूची में काफी विस्तार हुआ है, सूचीबद्ध निर्माताओं की संख्या शुरुआती वर्षों में मुट्ठी भर से बढ़कर 100 हो गई है और अब 2025 में 123 हो गई है। यह विस्तार भारत के सौर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर बढ़ते निवेश और औद्योगिक क्षमता को दर्शाता है।

(ii) दिसंबर 2024 में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सौर पीवी सेलों के लिए ALMM सूची-II को शामिल करने के लिए ALMM आदेश 2019 में

संशोधन किया, जिससे इस ढाँचे का विस्तार मॉड्यूल से आगे बढ़ गया। यह समावेशन संपूर्ण सौर मूल्य श्रृंखला में गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया को और मज़बूत करता है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत का नेतृत्व और मज़बूत होता है।

3. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने प्रभावशाली संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर और आत्मनिर्भरता पर प्रकाश डाला।

भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक मार्मिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने देश के लचीलेपन, लोकतांत्रिक मूल्यों और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर प्रकाश डाला। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में निर्णायक प्रतिक्रिया की सराहना की, समावेशी विकास पर ज़ोर दिया और नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के चिरस्थायी सिद्धांतों की याद दिलाई।

- **राष्ट्रपति मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर—22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की लक्षित सैन्य प्रतिक्रिया—को राष्ट्रीय संकल्प और तत्परता का एक सशक्त प्रदर्शन बताया। 7 मई को चलाए गए इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में नौ शिविरों में 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। भारत के रणनीतिक संयम पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने स्वदेशी आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल प्रणालियों के इस्तेमाल और जवाबी मिसाइल व ड्रोन हमलों के खिलाफ देश की सफल रक्षा की सराहना की।**

- **राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए एक "परीक्षण" बताया और भारत की बढ़ती तकनीकी आत्मनिर्भरता की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि कैसे देश द्वारा स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के उपयोग ने उसकी वैश्विक रणनीतिक विश्वसनीयता को मज़बूत किया है।**

Key Points:-

(i) राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत की मज़बूत आर्थिक स्थिति का ज़िक्र किया और 6.5% की GDP विकास दर, नियंत्रित मुद्रास्फीति और बढ़ते निर्यात का ज़िक्र किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि विकास सभी वर्गों तक पहुँचना चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अवसरों तक समान पहुँच शामिल है—न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों पर आधारित।

(ii) भारत की प्रगति में विश्वास व्यक्त करते हुए, राष्ट्रपति ने नागरिकों से स्थानीय उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने इस सांस्कृतिक बदलाव को भारत के लोकतांत्रिक और विकासात्मक चरित्र का अभिन्न अंग बताया।

(iii) राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संवैधानिक स्तंभों के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। उन्होंने नागरिकों को याद दिलाया कि वे स्वतंत्रता के बलिदानों को कभी न भूलें और संविधान एवं लोकतंत्र का सम्मान करें। गरिमा, एकजुटता और समान अवसर के स्थायी मूल्यों को भारत के भविष्य का मार्गदर्शन करना चाहिए।

4. प्रधानमंत्री मोदी ने ₹99,446 करोड़ की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च की, जिसका लक्ष्य 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करना है।

15 अगस्त, 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) की घोषणा की—जो 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजना है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का लक्ष्य दो वर्षों में औपचारिक क्षेत्र में 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करना है, जिससे पहली बार नौकरी पाने वालों को सहायता मिलेगी और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

- **PM-VBRY पूर्ववर्ती रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना का स्थान लेगी और यह 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 तक प्रभावी रहेगी - यह दो वर्ष की कार्यान्वयन अवधि है जिसका उद्देश्य रोजगार वृद्धि को औपचारिक बनाना और बढ़ावा देना है।**

- **इस योजना को 99,446 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया है और इसका लक्ष्य 3.5 करोड़ से अधिक औपचारिक नौकरियां सृजित करना है, जिनमें से लगभग 1.92 करोड़ नौकरियां पहली बार कार्यबल में प्रवेश करने वालों, विशेषकर युवाओं के लिए हैं।**

Key Points:-

(i) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पंजीकृत नए कर्मचारियों, जिनकी मासिक आय ₹1 लाख तक है, को एक महीने के ईपीएफ वेतन (₹15,000 तक) के बराबर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह राशि दो किश्तों में दी जाती है - 6 और 12 महीने की निरंतर नौकरी के बाद, साथ ही एक अनिवार्य वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी चलाया जाता है। इस राशि का एक हिस्सा वित्तीय नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बचत योजना में आवंटित किया जाता है।

(ii) इस योजना के तहत, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ पंजीकृत नियोक्ता जो अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं, उन्हें प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए मासिक प्रोत्साहन मिलेगा - 10,000 रुपये तक कमाने वाले कर्मचारियों के लिए 1,000 रुपये; 10,001 रुपये से 20,000 रुपये के बीच कमाने वालों के लिए 2,000 रुपये; और 20,001 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच कमाने वालों के लिए 3,000 रुपये - विनिर्माण क्षेत्र को ये लाभ 4 साल तक की विस्तारित अवधि के लिए प्राप्त होंगे।

(iii) यह योजना रोज़गार को औपचारिक बनाने, रोज़गार बनाए रखने में सुधार लाने और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने पर ज़ोर देती है। यह सभी क्षेत्रों को कवर करती है—विशेष रूप से विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए—और व्यापक "विकसित भारत" मिशन का हिस्सा है। इसके कार्यान्वयन में आधार और पैन से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शामिल है, और इसे विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता सत्रों के साथ लागू किया गया है, जिसमें नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों, दोनों का मार्गदर्शन करने के लिए EPFO द्वारा संचालित सेमिनार भी शामिल हैं।

5. केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने तमिलनाडु में वन वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली 'HAWK' का शुभारंभ किया।

अगस्त 2025 में, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (MoEF&CC) कीर्ति वर्धन सिंह ने वन्यजीव अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए तमिलनाडु (TN) के लिए एक डिजिटल वन एवं वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली, 'होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल (HAWK)' का एक अनुकूलित संस्करण लॉन्च किया। इस लॉन्च के साथ, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बाद, इस प्रणाली को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया।

• HAWK को वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि वन विभागों को वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित करने वाली अवैध गतिविधियों की निगरानी, विश्लेषण और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान किया जा सके। इसका मुख्य लक्ष्य पूरे तमिलनाडु में वन निगरानी को बढ़ाना और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना है।

• इस प्रणाली को भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट (WTI) ने जापानी सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सेवा प्रदाता निप्पॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन (एनटीटी) डेटा के सहयोग से विकसित किया है। यह सहयोग वन्यजीव अपराध प्रबंधन को मज़बूत करने के लिए उन्नत तकनीक और विश्लेषण प्रदान करता है।

Key Points:-

(i) HAWK चार एकीकृत मॉड्यूलों के माध्यम से कार्य करता है: पेरेग्रीन, शिकरा, हैरियर और केस्ट्रेल। वर्तमान में, तमिलनाडु में केवल पेरेग्रीन और शिकरा मॉड्यूल ही लागू किए गए हैं, जिनका ध्यान वन्यजीव अपराधों की निगरानी, रिपोर्टिंग और उनके विरुद्ध निवारक उपायों पर केंद्रित है।

(ii) यह प्रणाली अपराधियों के नाम, स्थान और उपनाम निकालने के लिए नामित इकाई पहचान (NER) का उपयोग करती है। यह आपराधिक संबंधों का मानचित्रण करने के लिए नेटवर्क विश्लेषण और ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके संभावित शिकार स्थलों की पहचान करने के लिए पूर्वानुमानात्मक मॉडलिंग का भी उपयोग करती है, जिससे सक्रिय वन प्रबंधन संभव होता है।

(iii) तमिलनाडु से पहले, HAWK को केरल और कर्नाटक में लागू किया गया था। तमिलनाडु में इसकी शुरुआत से राज्य के वन विभाग की वन्यजीव अपराधों पर अंकुश लगाने, निगरानी बढ़ाने और लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा करने की क्षमता मज़बूत हुई है, और यह अन्य भारतीय राज्यों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करता है।

BANKING & FINANCE

1. RBI CTS बैंकिंग प्रणाली में दो चरणों में सतत समाशोधन और निपटान शुरू करेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) में एक परिवर्तनकारी उन्नयन की घोषणा की है, जिसके तहत बैच प्रोसेसिंग से लेकर ऑन-रियलाइज़ेशन सेटलमेंट तक निरंतर समाशोधन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह दो चरणों में लागू होगा और 4 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगा, जिसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में चेक प्रोसेसिंग में भारी तेज़ी लाना है।

- **आरबीआई निरंतर समाशोधन प्रणाली को दो अलग-अलग चरणों में लागू करेगा। पहला चरण 4 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगा, जिसमें यह अनिवार्य होगा कि प्रस्तुत किए गए चेक पूरे व्यावसायिक घंटों के दौरान लगातार स्कैन, प्रेषित और समाशोधन गृह में जमा किए जाएँ। दूसरा चरण 3 जनवरी, 2026 से शुरू होगा, जिसमें निपटान समय-सीमा को और अधिक परिष्कृत करके चेक की समाप्ति को कुछ ही घंटों में सीमित कर दिया जाएगा।**

- **पारंपरिक विलंबित बैच प्रोसेसिंग के बजाय, अब चेकों का प्रसंस्करण वास्तविक समय में किया जाएगा। नई प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि चेक प्रस्तुत होने के तुरंत बाद उसे स्कैन करके अग्रेषित कर दिया जाए। आहर्ता प्राप्त करने वाले बैंकों को उसी दिन शाम 7 बजे तक (मान्य या अनादरित) पुष्टि करनी होगी, अन्यथा उन्हें स्वीकृत मान लिया जाएगा।**

Key Points:-

(i) मौजूदा व्यवस्था के तहत, चेक क्लियरिंग में दो कार्यदिवस तक का समय लग सकता है। संशोधित CTS, चेक इमेज और डेटा की निरंतर प्रोसेसिंग को लागू करके इस चक्र को घटाकर मात्र कुछ घंटों का कर देगा।

(ii) इस कदम से धन प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा समय में उल्लेखनीय कमी आने से ग्राहक अनुभव में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। इससे बैंकिंग दक्षता में भी सुधार होगा, निपटान जोखिमों पर अंकुश लगेगा, परिचालन लागत कम होगी और तरलता में वृद्धि होगी - जिससे चेक प्रसंस्करण की गति NEFT (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण) और RTGS (वास्तविक समय सकल निपटान) के करीब पहुँच जाएगी।

(iii) चरणबद्ध दृष्टिकोण बैंकों को बुनियादी ढाँचे में सुधार, परिचालन को बेहतर बनाने और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक समय प्रदान करता है। नए सीटीएस प्रोटोकॉल को निर्बाध रूप से अपनाने के लिए आरबीआई से जल्द ही विस्तृत कार्यान्वयन दिशानिर्देश आने की उम्मीद है।

2. HDFC एर्गो जनरल ने 'मिसिंग मिडिल' के लिए किफायती स्वास्थ्य बीमा लॉन्च करने के लिए फोनपे के साथ साझेदारी की।

13 अगस्त, 2025 को, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड - HDFC लिमिटेड और एर्गो इंटरनेशनल एजी के बीच एक संयुक्त उद्यम) ने भारत में वंचित नागरिकों के लिए कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से कम लागत वाली स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने के लिए फोनपे के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की।

- **यह सहयोग भारत के 'लापता मध्य' वर्ग को लक्षित करता है - 18 से 30 वर्ष की आयु के लगभग**

40 करोड़ नागरिक - जो सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं और मौजूदा निजी बीमा योजनाओं दोनों के दायरे से बाहर हैं।

• इस पहल का उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वर्ग के युवा वयस्कों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा को अधिक सुलभ और किफायती बनाना है।

Key Points:-

(i) इस योजना के अंतर्गत, 3 लाख रुपये की बीमा राशि के लिए प्रीमियम मात्र 12 रुपये प्रतिदिन (4,380 रुपये वार्षिक) से शुरू होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले पहली बार खरीदार भी बिना किसी महत्वपूर्ण वित्तीय तनाव के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल कवरेज का उपयोग कर सकते हैं।

(ii) स्वास्थ्य बीमा को फोनपे मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सीधे खरीदा, नवीनीकृत और प्रबंधित किया जा सकता है, जिससे उपयोगकर्ता अपने स्मार्टफोन से पॉलिसी दस्तावेजीकरण, दावों और लाभों को आसानी से संभाल सकते हैं।

(iii) पॉलिसी लाभों में अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क में कैशलेस अस्पताल में भर्ती, बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) परामर्श, निर्दिष्ट उपभोग्य सामग्रियों के लिए कवरेज, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और वेक्टर जनित रोगों से सुरक्षा शामिल है, जिससे लक्षित जनसांख्यिकी के लिए निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा दोनों तक पहुंच मजबूत होती है।

3. SBI लाइफ ने लचीले कवरेज विकल्पों के साथ "स्मार्ट शील्ड प्लस" टर्म इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया।

14 अगस्त, 2025 को, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (SBI लाइफ), भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और BNP पारिबा कार्डिफ के बीच एक संयुक्त उद्यम (JV) ने "SBI लाइफ-स्मार्ट शील्ड प्लस" पेश किया, जो एक भविष्य के लिए तैयार टर्म इंश्योरेंस प्लान है, जो लचीले विकल्पों और जीवन स्तर के लाभों के साथ ग्राहकों की बढ़ती सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।

• SBI लाइफ-स्मार्ट शील्ड प्लस एक व्यक्तिगत, नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, शुद्ध जोखिम वाली टर्म इंश्योरेंस योजना है। इसे उच्च स्तर की अनुकूलनशीलता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे ग्राहक अपनी वित्तीय ज़िम्मेदारियों और व्यक्तिगत लक्ष्यों में बदलाव के अनुसार कवरेज को समायोजित कर सकते हैं।

• यह योजना तीन अलग-अलग कवरेज विकल्प प्रदान करती है: लेवल कवर, जहां बीमित राशि पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान स्थिर रहती है; बढ़ता कवर लाभ, जहां बीमित राशि 5% वार्षिक की साधारण दर से बढ़ती है (मूल बीमित राशि के 100% तक सीमित); और फ्यूचर प्रूफिंग लाभ के साथ लेवल कवर, जो विवाह, बच्चे के जन्म और घर खरीदने जैसी विशिष्ट जीवन घटनाओं पर कवरेज बढ़ाने की अनुमति देता है।

Key Points:-

(i) फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट के साथ लेवल कवर के तहत, पॉलिसीधारक जीवन के महत्वपूर्ण चरणों में अतिरिक्त मेडिकल अंडरराइटिंग के बिना अपना कवरेज बढ़ा सकते हैं, जिससे समय के साथ वित्तीय जिम्मेदारियों के बढ़ने पर निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

(ii) इस योजना का जीवन बीमा, संपूर्ण जीवन विकल्प के लिए 100 वर्ष की आयु तक विस्तारित है, जो आजीवन सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि अन्य टर्म विकल्प 79 वर्ष की आयु तक कवरेज प्रदान करते हैं। यह लचीलापन ग्राहकों को अपने दीर्घकालिक योजना लक्ष्यों के अनुरूप अवधि चुनने में सक्षम बनाता है।

(iii) अपने लचीले डिजाइन, विविध कवरेज संरचनाओं और माइलस्टोन-आधारित लाभों के साथ, एसबीआई लाइफ-स्मार्ट शील्ड प्लस का उद्देश्य ग्राहकों को व्यापक टर्म सुरक्षा प्रदान करना है जो उनकी जीवन यात्रा के साथ विकसित होती है, जिससे अनिश्चित समय के दौरान परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

MOUs and Agreement

1. IGNCA और BSIP ने भारत की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत को एकीकृत करने के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

अगस्त 2025 में, संस्कृति मंत्रालय के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoS&T) के तहत बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान (BSIP) ने विज्ञान-संस्कृति एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- **समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह IGNCA, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जो भारत की वैज्ञानिक प्रगति और उसकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक एकीकृत मंच बनाने के उद्देश्य से की गई पहली राष्ट्रीय पहल है। यह सांस्कृतिक संस्थानों और वैज्ञानिक निकायों के बीच अंतःविषय सहयोग को बढ़ावा देने के भारत सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।**

- **इस समझौते को IGNCA के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी और BSIP के निदेशक प्रो. महेश जी. ठक्कर ने औपचारिक रूप दिया। इस सहयोग का समन्वयन नामित नोडल अधिकारियों - IGNCA के संरक्षण प्रभाग के प्रमुख एवं प्रोफ़ेसर डॉ. अचल पंड्या और BSIP की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. शिल्पा पांडे - द्वारा किया जाएगा, जिससे संयुक्त कार्यक्रमों का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।**

Key Points:-

(i) समझौता ज्ञापन का एक प्रमुख उद्देश्य संयुक्त अनुसंधान, दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण परियोजनाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक-वैज्ञानिक विरासत का संरक्षण करना है। इसमें स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों की सुरक्षा, पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन और पुराविज्ञान संबंधी निष्कर्षों को सांस्कृतिक आख्यानों के साथ एकीकृत करके प्रामाणिक और शोध-समर्थित विरासत सामग्री का निर्माण शामिल है।

(ii) यह साझेदारी हिमालय से कन्याकुमारी तक

लुप्तप्राय परंपराओं के संरक्षण के उद्देश्य से वृत्तचित्रों, प्रदर्शनियों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से जन-जन तक पहुँच बनाने पर भी ज़ोर देती है। ऐसी पहल विज्ञान, इतिहास और संस्कृति के बीच संबंधों के बारे में लोगों की समझ को मज़बूत करने में मदद करेंगी।

(iii) इस समझौते का एक उल्लेखनीय घटक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संसाधनों का डिजिटलीकरण है ताकि उन्हें शोधकर्ताओं, छात्रों और आम जनता के लिए व्यापक रूप से सुलभ बनाया जा सके। यह समझौता ज्ञापन, पर्यावरणीय परिवर्तन के संदर्भ में विरासत की व्यापक समझ के लिए पुराजलवायु अनुसंधान को सांस्कृतिक अध्ययनों के साथ जोड़कर, भारत के समुद्री इतिहास पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की जाँच करने वाली एक पहल, प्रोजेक्ट मौसम का भी सक्रिय रूप से समर्थन करेगा।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. महामहिम जीनत कुरैशी लक्जरी कूटनीति में GCC-भारत व्यापार आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।

अगस्त 2025 में, भारतीय अभिनेता, निर्माता और निवेशक महामहिम जीनत कुरैशी ने ग्लोबल चैंबर ऑफ कॉमर्स के तहत खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)-भारत व्यापार आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया, जिससे लक्जरी कूटनीति को मजबूती मिली और प्रीमियम आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिला।

- **माननीय जीनत कुरैशी GCC-भारत राजनयिक व्यापार निकाय का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों और उच्च स्तरीय आर्थिक कूटनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में एक अग्रणी उपलब्धि है।**

- **GCC-भारत व्यापार आयुक्त के रूप में, वह रणनीतिक व्यापार और सांस्कृतिक साझेदारी के माध्यम से भारत और GCC देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगी, विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में।**

- **उनका काम भारत के प्रीमियम उद्योगों - जैसे फैशन, आभूषण, ललित कला, आतिथ्य और लक्जरी रियल एस्टेट - और GCC के तेजी से बढ़ते लक्जरी बाजारों के बीच मजबूत संबंध बनाने पर केंद्रित होगा।**

Key Points:-

(i) खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) 1981 में स्थापित एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है, जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) शामिल हैं। यह सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण, राजनीतिक समन्वय और व्यापार सहयोग को बढ़ावा देता है।

(ii) यह नियुक्ति "लक्जरी कूटनीति" में एक मील का पत्थर है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र है जो सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को आर्थिक मूल्य के साथ जोड़ता है, जिससे भारत को अपने प्रीमियम ब्रांडों और कारीगरों को आकर्षक खाड़ी बाजारों में स्थापित करने में मदद मिलती है।

(iii) उनके नेतृत्व से नए व्यापार समझौतों, निवेश अवसरों और संयुक्त उद्यमों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है, जो जीसीसी में भारत की आर्थिक स्थिति

को मजबूत कर सकते हैं, जिससे लक्जरी और उच्च-अंत क्षेत्रों में दोनों क्षेत्रों को लाभ होगा।

2. श्रीनगर में प्रथम खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के लिए आधिकारिक शुभंकर के रूप में हिमालयन किंगफिशर का अनावरण किया गया।

अगस्त 2025 में, हिमालयन किंगफिशर को श्रीनगर की डल झील में 21-23 अगस्त तक आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के mascot के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस आयोजन में भारत भर से 400 से अधिक एथलीट जल-क्रीड़ा में अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करेंगे।

- **चमकीले नारंगी और नीले रंग का जीवंत हिमालयन किंगफिशर, उत्सव के आधिकारिक शुभंकर के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो रोमांच, प्रकृति और प्रतिस्पर्धात्मक भावना का प्रतीक है। यह पर्यावरण-अनुकूल खेलों, पर्यटन और युवा जुड़ाव का प्रतीक भी है।**
- **खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर की सुंदर डल झील में 21 से 23 अगस्त, 2025 तक आयोजित किया जाएगा - जो खेलो इंडिया कैलेंडर का विस्तार करने की सरकार की पहल का हिस्सा है।**
- **इस महोत्सव में पाँच जल-क्रीड़ाएँ शामिल हैं: नौकायन, कैनोइंग और कयाकिंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेसिंग और ड्रैगन बोट रेसिंग। इसके अलावा, वाटर स्कीइंग और स्वदेशी शिकारा दौड़ जैसे प्रदर्शन कार्यक्रम सांस्कृतिक आकर्षण बढ़ाएँगे।**

Key Points:-

(i) इस ओपन-एज राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से ज़्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। चयन राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा योग्यता-आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी देखरेख एक तकनीकी आचरण समिति करेगी।

(ii) यह महोत्सव भारत के खेल रोडमैप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा—यह शीतकालीन खेलों, पैरा खेलों, युवा खेलों और बीच खेलों के बाद 2025 में पाँचवें प्रमुख खेलो इंडिया आयोजन का प्रतिनिधित्व करता है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा SAI और जम्मू-कश्मीर खेल परिषद के सहयोग से आयोजित इस आयोजन का उद्देश्य डल झील को एक राष्ट्रीय जल क्रीड़ा केंद्र के रूप में स्थापित करना और साथ ही जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं के विकास को बढ़ावा देना है।

SPORTS

1. एस. रोहित कृष्णा भारत के 89वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने।

अगस्त 2025 में, चेन्नई, तमिलनाडु के 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र एस. रोहित कृष्णा ने अपना अंतिम ग्रैंडमास्टर (GM) मानदंड हासिल किया और आधिकारिक तौर पर भारत के 89वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए। जुलाई 2025 तक, उन्होंने FIDE (फेडरेशन इंटरनेशनेल डेस एचेक्स) रेटिंग 2516 प्राप्त कर ली, जो उनके शतरंज करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

• एस. रोहित कृष्णा ने कज़ाकिस्तान में अल्माटी मास्टर्स कोनायेव कप में 9 में से 6 अंक हासिल करके और 2500 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करके अपना अंतिम जीएम नॉर्म हासिल किया। अंतिम दौर में, उन्होंने अर्मेनियाई अंतर्राष्ट्रीय मास्टर आर्टुर दावत्यान को हराकर यह प्रतिष्ठित खिताब जीता।

• ग्रैंडमास्टर खिताब की ओर उनका सफ़र फरवरी 2025 में शुरू हुआ, जब उन्होंने होटल स्टॉकहोम नॉर्थ GM राउंड-रॉबिन टूर्नामेंट में 6.5/9 के अपराजित स्कोर के साथ अपना पहला GM नॉर्म हासिल किया। इसके बाद, जून 2025 में 25वें दुबई ओपन में उन्होंने अपना दूसरा जीएम नॉर्म हासिल किया, जिससे ग्रैंडमास्टर खिताब की ओर उनका रास्ता और मज़बूत हो गया।

• इस उपलब्धि से पहले, रोहित कृष्णा ने 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर (IM) का खिताब हासिल करके अपनी पहचान बना ली थी। इस शुरुआती सफलता ने अंतरराष्ट्रीय शतरंज सर्किट में उनकी निरंतरता और क्षमता का प्रदर्शन किया, जिसने उनके सर्वोच्च शतरंज खिताब तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया।

Key Points:-

(i) ग्रैंडमास्टर योग्यता के लिए FIDE मानदंडों के अनुसार, एक खिलाड़ी को आधिकारिक FIDE-रेटेड स्पर्धाओं में मज़बूत खिताब वाले खिलाड़ियों के खिलाफ तीन ग्रैंडमास्टर मानदंड हासिल करने होंगे, साथ ही 2500 एलो रेटिंग सीमा पार करनी होगी। रोहित ने इन आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे वह भारतीय शतरंज के सबसे तेज़ी से उभरते सितारों में से एक बन गए।

(ii) इस उपलब्धि के साथ, भारत में अब 89 शतरंज ग्रैंडमास्टर हो गए हैं, जिससे वैश्विक शतरंज में देश की उपस्थिति मजबूत हुई है।

(iii) रोहित कृष्णा की सफलता शतरंज की महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा में योगदान देती है, जो विश्वनाथन आनंद जैसे अग्रदूतों की विरासत का अनुसरण करती है, साथ ही खिलाड़ियों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती है।

IMPORTANT DAYS

1. 14 अगस्त 2025 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया, जिसमें 1947 के विभाजन पीड़ितों को सम्मानित किया गया।

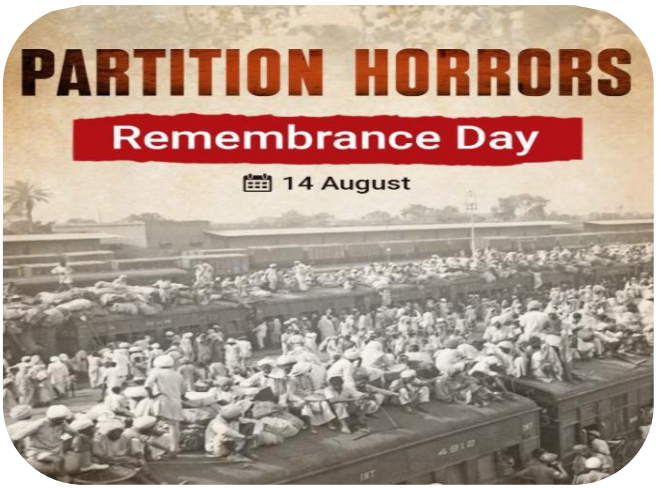

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस (हिंदी: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस) भारत में प्रतिवर्ष 14 अगस्त को 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के पीड़ितों के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन मानव इतिहास के सबसे बड़े प्रवासों में से एक से प्रभावित लोगों के दर्द, पीड़ा, साहस और दृढ़ता को दर्शाता है। 2025 में, यह दिवस पाँचवाँ वार्षिक उत्सव होगा।

• 14 अगस्त, 2025 को भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का पाँचवाँ वार्षिक स्मरणोत्सव मनाया जाएगा। यह दिन पाकिस्तान के

स्वतंत्रता दिवस के साथ मेल खाता है और 1947 की दुखद घटनाओं पर चिंतन करने तथा विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा और सामूहिक विस्थापन के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने का एक पवित्र अवसर है।

• इस दिन को आधिकारिक तौर पर 2021 में प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया था। पहला पालन 14 अगस्त, 2021 को हुआ था। इसका उद्देश्य विभाजन के पीड़ितों को सम्मानित करना और भारत और पाकिस्तान में लाखों लोगों के जीवन पर इसके गहन प्रभाव को स्वीकार करना है।

• विभाजन मुस्लिम लीग की माँगों, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति और मुहम्मद अली जिन्ना के सांप्रदायिक रुख जैसे कारकों के कारण हुआ। ब्रिटिश भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जिससे व्यापक सांप्रदायिक हिंसा और बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया।

Key Points:-

(i) विभाजन के कारण भयंकर सांप्रदायिक हिंसा हुई, बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ और यह इतिहास में दर्ज सबसे बड़े मानव प्रवासों में से एक बन गया। आँकड़ों से पता चलता है कि लगभग 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए, जिनमें से लगभग 60 लाख गैर-मुस्लिम पश्चिमी पाकिस्तान छोड़कर चले गए और लगभग 65 लाख मुसलमान पंजाब और दिल्ली जैसे क्षेत्रों से पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए।

(ii) 3 जून, 1947 को भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की औपचारिक घोषणा की। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमाएँ सिरिल रेडक्लिफ़ ने खींची थीं, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों में बड़े पैमाने पर विस्थापन, संपत्ति की हानि और मानवीय पीड़ा हुई।

(iii) 2025 में, संस्कृति मंत्रालय, रेल मंत्रालय (MoR) के साथ साझेदारी में, देश भर में, विशेष रूप से रेलवे स्टेशनों पर, विभाजन के दौरान झेली गई कठिनाइयों को दर्शाने के लिए प्रदर्शनियाँ आयोजित करेगा। इन पहलों का उद्देश्य नागरिकों को ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में शिक्षित करना और प्रभावित आबादी के धैर्य को याद करना है।

DEFENCE

1. प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के स्वदेशी लौह गुंबद शैली के रक्षा कवच 'मिशन सुदर्शन चक्र' का शुभारंभ किया।

15 अगस्त, 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान कृष्ण के पौराणिक चक्र से प्रेरित एक अत्याधुनिक वायु-रक्षा पहल, मिशन सुदर्शन चक्र का उद्घाटन किया। सामरिक, नागरिक और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया यह मिशन रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की भारत की महत्वाकांक्षा को रेखांकित करता है।

• महाभारत के सुदर्शन चक्र से प्रेरणा लेते हुए—जिसका इस्तेमाल भगवान कृष्ण ने सूर्य की रोशनी रोकने और अर्जुन की सहायता के लिए किया था—यह मिशन आध्यात्मिक प्रतीकवाद और उन्नत रक्षा, दोनों का प्रतीक है। इस शक्तिशाली कल्पना पर आधारित, इस पहल का उद्देश्य भविष्य की स्वदेशी तकनीक के माध्यम से शक्ति, सटीकता और सुरक्षा का प्रदर्शन करना है।

• "मिशन सुदर्शन चक्र" इज़राइल के आयरन डोम जैसा एक शक्तिशाली, बहु-स्तरीय वायु-रक्षा कवच तैयार करता है। इसका उद्देश्य: अस्पतालों, परिवहन केंद्रों और पूजा स्थलों सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के लिए हवाई खतरों का पता लगाना, उन्हें बेअसर करना और उन पर जवाबी कार्रवाई करना।

• इस मिशन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह पूरी तरह से भारतीय इंजीनियरिंग और अनुसंधान पर निर्भर है। इसका उद्देश्य पूरी तरह से घरेलू विशेषज्ञता के माध्यम से इस प्रणाली का निर्माण, विकास और तैनाती करना है, जिससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को बल मिलेगा।

Key Points:-

(i) मिशन सुदर्शन चक्र, व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच (राष्ट्रीय सुरक्षा कवच) ढाँचे का एक रणनीतिक घटक है। यह प्रधानमंत्री मोदी के 79वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में घोषित सुरक्षा उन्नयन के एक समूह का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य प्रतिरोधक क्षमता और तकनीकी स्वतंत्रता को बढ़ाना है।

(ii) 2035 तक पूरा होने की योजना के साथ, मिशन सुदर्शन चक्र भारत की दीर्घकालिक रक्षा दिशा के लिए मंच तैयार करता है—AI-सक्षम प्लेटफ़ॉर्म, निर्देशित ऊर्जा हथियार, साइबर-इंटरसेप्ट और अगली पीढ़ी के युद्धक्षेत्र लचीलेपन की ओर एक बदलाव। यह सैन्य नवाचार और बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण के एक नए युग का संकेत देता है।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. चीन ने IoT और वाहन संचार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए गीली-04 उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया।

अगस्त 2025 में, चीन ने वैश्विक इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) कनेक्टिविटी, समुद्री संचालन और अंतर-वाहन संचार को बढ़ाने के लिए गीली फ्यूचर मोबिलिटी कॉन्स्टेलेशन (GEESATCOM) के तहत गीली-04 उपग्रहों के चौथे बैच का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इस मिशन में 11 लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) उपग्रहों को शेडोंग प्रांत के रिझाओ के पास एक अपतटीय प्लेटफॉर्म से स्मार्ट ड्रैगन-3 (SD-3) रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया।

• इस मिशन को झेजियांग Geely होल्डिंग ग्रुप की वाणिज्यिक एयरोस्पेस सहायक कंपनी, गीस्पेस द्वारा अंजाम दिया गया, जिसका उपग्रह प्रक्षेपण संचालन ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से किया गया। गीस्पेस 2018 से अपने LEO समूह का संचालन कर रहा है, जिसका मुख्य ध्यान स्वायत्त ड्राइविंग, उच्च-सटीक स्थिति निर्धारण और IoT सेवाओं पर है।

• इस प्रक्षेपण के साथ, गीस्पेस ने अपने गीली-04 गीसैटकॉम IoT समूह को 30 से बढ़ाकर 41 कर दिया है। कंपनी का लक्ष्य 2025 के अंत तक 72 उपग्रहों का नेटवर्क स्थापित करना है, जिससे निर्बाध वैश्विक IoT कवरेज संभव हो सके।

• स्मार्ट ड्रैगन-3 (SD-3) रॉकेट, जिसे जीलोंग-3 के नाम से भी जाना जाता है, ने प्रक्षेपण यान का काम किया। 31 मीटर लंबा, 140 टन वज़नी और ठोस प्रणोदक से युक्त, एसडी-3 500 किलोमीटर की सूर्य-

तुल्यकालिक कक्षा (SSO) में 1,500 किलोग्राम तक के पेलोड पहुँचाने में सक्षम है।

Key Points:-

(i) चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी (CALT) द्वारा विकसित, SD-3 रॉकेट को तीव्र तैनाती और लागत-प्रभावी अंतरिक्ष अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रक्षेपण ने SD-3 श्रृंखला की छठी उड़ान को चिह्नित किया, जिसने वाणिज्यिक उपग्रह अभियानों के लिए इसकी विश्वसनीयता को और पुख्ता किया।

(ii) Geely लियो सैटेलाइट प्रोग्राम समुद्री निगरानी, स्वायत्त वाहन नेविगेशन और रिमोट सेंसिंग सहित विभिन्न अनुप्रयोगों का समर्थन करता है। ये उपग्रह भूमि, समुद्र और वायु-आधारित प्रणालियों के बीच रीयल-टाइम डेटा स्थानांतरण को बढ़ाते हैं, जिससे परिवहन, रसद और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को लाभ होता है।

(iii) चीन द्वारा गीली उपग्रह समूह की त्वरित तैनाती, वैश्विक अंतरिक्ष-आधारित IoT सेवाओं में अग्रणी बनने की उसकी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। यह पहल चीन के वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र को भी मज़बूत करेगी, जो देश के दीर्घकालिक अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विकास लक्ष्यों के अनुरूप है।

2. एस्ट्रोफेल एयरोस्पेस और इन-स्पेस ने हाल ही में पुन: प्रयोज्य रॉकेट इंजन विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

एस्ट्रोफेल एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) – जो अंतरिक्ष विभाग (DoS) के अंतर्गत एक नोडल निकाय है – के साथ पुन: प्रयोज्य रॉकेट इंजन तकनीक को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक रूपरेखा समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को 13 अगस्त 2025 को औपचारिक रूप दिया गया।

- **IN-SPACe के अध्यक्ष डॉ. पवन गोयनका और IN-SPACe में कार्यक्रम प्रबंधन एवं प्राधिकरण के निदेशक डॉ. प्रफुल्ल कुमार जैन की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।**

- **एस्ट्रोफेल एयरोस्पेस को सिस्टम-स्तरीय परीक्षण, योग्यता समर्थन और तकनीकी समीक्षा के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त होगी, जिसमें टर्बोपंप, इंजन मॉड्यूल और अन्य उप-प्रणालियां जैसे महत्वपूर्ण घटक शामिल होंगे।**

Key Points:-

(i) इस समझौता ज्ञापन के तहत, एस्ट्रोफेल एक संयुक्त परियोजना कार्यान्वयन योजना (JPIP) के माध्यम से इसरो विशेषज्ञों के साथ सहयोग करेगा, जो परियोजना-विशिष्ट डिजाइन सत्यापन, उप-प्रणाली

विकास और पुन: प्रयोज्य रॉकेट प्रणोदन के लिए अभियान परीक्षण की सुविधा प्रदान करेगा।

(ii) यह सहयोग रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक गैस अनुप्रयोगों में दोहरे उपयोग की क्षमता वाले महत्वपूर्ण उप-प्रणालियों — जिनमें वाल्व, टर्बो पंप और एवियोनिक्स प्रणालियाँ शामिल हैं — के विकास पर केंद्रित है। इससे एस्ट्रोफेल को स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाते हुए एयरोस्पेस क्षेत्र से परे नवाचार करने में मदद मिलेगी।

(iii) यह उपलब्धि एस्ट्रोफेल द्वारा ₹6.84 करोड़ की फंडिंग सफलतापूर्वक जुटाने के बाद मिली है, और 50 लाख अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त राशि जुटाने की योजना है। कंपनी ने इससे पहले 15 अगस्त 2023 को एक उपलब्धि हासिल की थी, और बिना किसी बाहरी पूंजी सहायता के सेमी-क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली कुछ भारतीय स्टार्टअप्स में से एक बन गई थी।

OBITUARY

1. स्व-शिक्षित भाषाविद् और शब्दकोश निर्माता नजत्तेल्या श्रीधरन का निधन हो गया।

13 अगस्त, 2025 को, प्रसिद्ध स्व-शिक्षित भाषाविद् नजत्तेल्य श्रीधरन का 87 वर्ष की आयु में केरल के कन्नूर में निधन हो गया। 1938 में केरल के थालास्सेरी में जन्मे श्रीधरन को चार द्रविड़ भाषाओं को एकीकृत करने वाले 860 पृष्ठों के ऐतिहासिक शब्दकोश, चतुर द्रविड़ भाषा पधपरिचयम, के संकलन के लिए जाना जाता है।

- **नजत्तेल्य श्रीधरन ने बिना किसी औपचारिक भाषाई प्रशिक्षण के, 25 वर्षों से अधिक समय तक कोश-लेखन को समर्पित किया। उनकी महान कृति ने मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु को जोड़ा, जो द्रविड़ भाषाई विरासत में एक दुर्लभ योगदान है।**

- **उनका कैरियर केरल लोक निर्माण विभाग (PWD) और बाद में सिंचाई विभाग में ब्लूप्रिंटिंग कर्मचारी के रूप में शुरू हुआ, 1994 में सेवानिवृत्त होने से पहले। सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने खुद को पूरी तरह से अपने शब्दकोश परियोजना के लिए समर्पित कर दिया।**

- **चतुर द्रविड़ भाषा पधपरिचयम् का पहला प्रकाशन नवंबर 2020 में केरल भाषा संस्थान द्वारा किया गया था। पहले संस्करण की 500 प्रतियाँ थीं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत ₹4,000 थी, जो तुरंत बिक गईं।**

Key Points:-

(i) केरल भाषा संस्थान द्वारा मई 2023 में एक संशोधित और विस्तारित दूसरा संस्करण जारी किया गया, जिससे आधुनिक शब्दकोश में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उनकी विरासत को मजबूती मिली।

(ii) शब्दकोश लेखन के अलावा, उन्होंने पुरोगमना कला साहित्य संघम (प्रगतिशील कला और साहित्यिक संघ) के कन्नूर तालुक अध्यक्ष के रूप में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई और एनजीओ यूनियन के राज्य परिषद सदस्य भी रहे।

(iii) उनके जीवन और समर्पण को नंदन द्वारा निर्देशित पुरस्कार विजेता फिल्म "ड्रीमिंग ऑफ वर्ड्स" में दर्शाया गया, जिसे 2021 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार - विशेष जूरी उल्लेख प्राप्त हुआ। उन्हें डॉ. टी.पी. सुकुमारन मास्टर पुरस्कार और डॉ. हरमन

गुंडर्ट पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया।

2. भारतीय ओलंपिक हॉकी पदक विजेता डॉ. वेस पेस का 14 अगस्त, 2025 को निधन हो गया।

14 अगस्त, 2025 को भारत ने पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता डॉ. वेस पेस के निधन पर शोक व्यक्त किया। डॉ. वेस पेस का 80 वर्ष की आयु में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में निधन हो गया। वे प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के पिता भी थे।

- **डॉ. वेस पेस का जन्म 30 अप्रैल, 1945 को गोवा में हुआ था। उन्होंने 1966 में हैम्बर्ग इंटरनेशनल कप में भारतीय हॉकी टीम के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की, जिससे उनके शानदार खेल करियर की शुरुआत हुई।**

- **उन्होंने बार्सिलोना, स्पेन में आयोजित 1971 हॉकी विश्व कप और म्यूनिख, पश्चिम जर्मनी में आयोजित 1972 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीते, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान मिला।**

Key Points:-

(i) डॉ. पेस ने एशियाई क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और भारतीय डेविस कप टेनिस टीम में खेल चिकित्सा के डॉक्टर के रूप में कार्य किया, तथा विभिन्न विषयों में अपनी विशेषज्ञता प्रदान की।

(ii) उन्होंने 1996 से 2002 तक भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ के अध्यक्ष का पद संभाला और प्रतिष्ठित कलकत्ता क्रिकेट और फुटबॉल क्लब में नेतृत्व की भूमिका निभाई, जिससे खेल प्रशासन में उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ।

(iii) अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के अलावा, डॉ. वेस पेस को भारतीय खेलों में उनके योगदान और भारत के सबसे प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ियों में से एक लिएंडर पेस के पिता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने हॉकी और टेनिस दोनों में एक स्थायी विरासत छोड़ी।

Static GK

Ministry of Steel (MoS)	केंद्रीय मंत्री: श्री एच. डी. कुमारस्वामी	मुख्यालय: नई दिल्ली
RBI	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: मुंबई
China	राजधानी: बीजिंग	राष्ट्रपति: शी जिनपिंग
IN-SPACe	अध्यक्ष: डॉ. पवन कुमार गोयनका	मुख्यालय: अहमदाबाद
Tamil Nadu	मुख्यमंत्री: एम के स्टालिन	राज्यपाल: आर. एन. रवि